

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस ०एस०अली

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक १२१७-एक/२००४ - विरुद्ध आदेश दिनांक ३१-५-२००४ पारित क्षारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक १६६/१९९९-२००० अपील

ईश्वरहीन पुत्र जागेश्वर कोठवार

ग्राम कल्याणपुर तहसील मैहर

जिला सतना मध्य प्रदेश

— अपीलांट

विरुद्ध

१ - सरपंच, ग्राम पंचायत कल्याणपुर तहसील मैहर

२ - मध्य प्रदेश शासन

— रिस्पाण्डेन्टस्

(अपीलांट के अभिभाषक श्री राकेश कुमार निगम)

(रिस्पोन्स के विरुद्ध पूर्व से एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक ०७ - ६ - २०१७ को पारित)

यह अपील आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र०क० १६६/९९-२००० अपील में पारित आदेश दिनांक ३१-५-२००४ के विरुद्ध मध्य प्रदेश मूँ राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ४४ के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण का सारोंश यह है कि रिस्पोन्स क्रमांक १ ने ग्राम पंचायत की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ग्राम कल्याणपुर की भूमि सर्वे नंबर ३५ रकमा १३.३७८ हैक्टर राजस्व कागजात में मध्य प्रदेश शासन के नाम है। मौके पर भूमि रिक्त है इसलिये गॉव के नवयुवक, बच्चों के खेल कूद एवं आवास के लिये सुरक्षित की जावे। कलेक्टर सतना ने प्रकरण क्रमांक ३ अ ५९/९९-२००० पैजीबद्ध किया तथा तहसीलदार मैहर से स्थल की जाँच कराई।

इस्तहार प्रकाशन उपरांत आपत्ति न आने से आदेश दिनांक ७-१२-१९९९ पारित किया तथा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार भूमि सर्वे क्रमांक ३५ में से



रकबा 1.045 हैक्टर आवादी के लिये तथा 1.045 हैक्टर खेल के मैदान के लिये कुल रकबा 2.090 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) सुरक्षित कर दिया। कलेक्टर के आदेश दिनांक 7-12-99 के विलम्ब अपीलांट ने प्रथम अपील आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की। आयुक्त, रीवा संभाग ने प्रकरण क्रमांक 166/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2004 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4/ अपील मेमो में अंकित आधारों के क्रम में अपीलांट के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये, जिनके अवलोकन के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का भी अवलोकन किया गया। रिपोर्ट सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

5/ अपीलांट के अभिभाषक का तर्क है कि अपीलांट को कलेक्टर सतना वे सुनवाई का मौका नहीं दिया है जबकि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर लम्बे समय से कब्जा चला आ रहा है इसलिये कलेक्टर का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप न होने से निरस्त किया जाय। कलेक्टर सतना के प्रकरण क्रमांक 3 अ-59/99-2000 के अवलोकन पर पाया गया कि सरपंच ग्राम कल्याणपुर की ओर से दिनांक 2-9-1998 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर पंचायत कल्याणपुर की भूमि सर्वे नंबर 35 रकबा 13.378 ह0 राजस्व कागजात ग्राम कल्याणपुर की भूमि सर्वे नंबर 35 रकबा 13.378 ह0 राजस्व कागजात में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज होने, मौके पर भूमि रिक्त पड़ी होने से गाँव में नवयुवक एवं बच्चों के खेल कूद एवं आवास के लिये सुरक्षित रखे जाने की मांग की गई है तथा आवेदन के साथ ग्राम पंचायत का प्रताव/ठहराव दिनांक 1-9-98 एवं ग्राम सभा की बैठक दिनांक 23-3-98 में लिये गये निर्णय वावत् पारित प्रताव/ठहराव की प्रति प्रस्तुत की गई, जिस पर से कलेक्टर सतना के प्रकरण क्रमांक 3 अ-59/99-2000 पंजीबद्ध करते हुये तहसीलदार मैहर से ग्राँके की जाँच कराई है। तहसीलदार मैहर ने जाँच के दौरान आपत्तियाँ आमंत्रण हेतु आम-इस्तहार दिनांक 5-1-99 को जारी किया है। इस्तहार की कार्यालयीन प्रति कलेक्टर के प्रकरण में संलग्न है जिसके पीछे पृष्ठ पर पुष्टिकरण में ग्रामीण भवानी सिंह, रामचरण, रामभजन, रामकिशोर, रामदीन, शीताराम, अच्छेलाल, भर्ड्यालाल, रामसुजान, रामकरन के हस्ताक्षर हैं। इस्तहार अनुसार 8-2-99

तक आपत्तियों आमंत्रित की गई हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 के अंतर्गत भूमि के मद परिवर्तन कार्यवाही में ग्रामीणों को व्यक्तिगत सूचना देने का प्रावधान नहीं है जिसके कारण अपीलांट के अभिभाषक यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

अपीलांट क्वारा बताये गये इस तथ्य पर विचार किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर उसका अतिकरण है। ग्राम कल्याणपुर की भूमि सर्वे नंबर 35 रक्बा 13.378 हैक्टर राजस्व कागजात में मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज है। तहसीलदार मेहर ने मौके पर भूमि रिक्त पड़ी होना प्रतिवेदित किया है। कलोकटर सतना के प्रकरण में हलका पटवारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एंव ग्राम कल्याणपुर के पंचान क्वारा तैयार कर प्रस्तुत किया गया पंचनामा संलग्न है जिसके अनुसार रक्बा 13.378 हैक्टर में से ग्रामीणों के आवास हेतु एंव खेल कूद के मैदान हेतु भूमि आरक्षित करने वावत् सहमति का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में ग्राम कल्याणपुर की भूमि सर्वे नंबर 35 रक्बा 13.378 हैक्टर चारागाह हेतु आरक्षित होने एंव सार्वजनिक हित की होने से अपीलांट का कष्ट होने अथवा न होने से अपीलांट को वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का रखत पहुंचने का प्रश्न ही नहीं है, जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 166/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2004 में निकाल गये निष्कर्ष यही हैं जिनमें फेर-बदल की गुंजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा क्वारा प्रकरण क्रमांक 166/1999-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-5-2004 उचित होने से यथावत् रखते हुये अपील निरस्त की जाती है।

(एस०एस०आली)

सदस्य

राजस्व मण्डल, म०प्र०

गवालियर